of national importance rather than regional importance. Unfortunately, the funds are now being diverted also. Even the funds of TTD are being diverted to the local Tirupati Municipality. This being a year of election year, now, the funds of the devotees, who have donated the funds for expansion of *Sanatana Dharma* or even development of the temple, these funds are being diverted. I urge the concerned authority and the Government to view the matter seriously because the feelings of the devotees and the feelings of the *Sanatana Dharma* people are being hurt. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. K. Laxman: Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu).

Vandalism at Sirhind Railway Station

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) : महोदय, आज आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं आज सदन के सामने एक संवेदनशील मुद्दा रखना चाहूंगा जो हमारे देश की लाइफ लाइन रेलवे से जुड़ा हुआ है। मैं पंजाब से आता हूं और पिछले महीने पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने अचानक ट्रेन कैंसिल होने पर पथराव किया और स्टेशन को भी डैमेज किया। यह समस्या सिर्फ पंजाब की ही नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले सूरत, गुजरात में भी stampede हुआ, क्योंकि वहां ओवरक्राउडिंग थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं भी देखी गई हैं, जब वंदे भारत या बाकी और ट्रेनों पर पथराव किया गया। यह विषय चिंताजनक है और रेलवे तथा यात्रियों की सेफ्टी को कम्प्रोमाइज करता है और इससे रेल हादसा बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। यदि आंकड़ों में देखा जाए तो पिछले 4 वर्षों में 1,360 करोड़ की रेलवे की संपत्ति का इस तरीके से नुकसान हुआ है। जब हम इसके कारणों में जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो समझ में यह आता है कि रेलवे स्टेशंस पर सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को गुस्सा आता है और वह इस तरीके से निकलता है। हालांकि यह गलत है, पर उनका गुस्सा इस तरीके से निकलता है।

सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। भारत सरकार ने सन् 1916 में दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कानून बनाया, लेकिन इस कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां अगर कहीं उड़ती हैं तो वह रेलवे स्टेशंस पर उड़ती हैं। हमारे हजारों रेलवे स्टेशंस में से ऐसे मुट्ठी पर रेलवे स्टेशंस होंगे जो डिसेबल्ड फ्रेंडली होंगे। वहां लिफ्ट की सुविधाएं नहीं हैं, प्रॉपर वॉशरूम की सुविधाएं नहीं हैं, वेटिंग रूम की सुविधाएं नहीं हैं। कई बार ट्रेन या तो आगे रुक जाती है या पीछे रुक जाती है, इसके कारण यात्री पैनिक में चढ़ते हैं और उससे भी

हादसे की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, ट्रेन्स लेट भी होंगी तथा और भी कई समस्याएं आएंगी, तो उसमें हम क्या सुविधाएं यात्रियों को देने जा रहे हैं?

इन सब बढ़ते हुए केसेज़ और कम फैसिलिटीज़ के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिए वह एक well strategy बनाए, ताकि हम तोड़-फोड़ और ऐसी ही अन्य घटनाओं को रोक सकें। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशंस का रिडेवलपमेंट प्लान चल रहा है, अपग्रेडेशन प्लान चल रहा है। उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा रेलवे स्टेशंस इस प्लान में शामिल किया जाए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Ashok Kumar Mittal: Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal) and Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu).

Need to address challenges of *Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana* (PM-JAY) Programme

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a very important question. The Ayushman Bharat, the PM-JAY, is a flagship programme of the Government. This noble initiative strives to give a comprehensive health coverage to the poor and vulnerable. But, in spite of five years from the starting of the programme, there still suffers several challenges which this entire Yojana faces like, low level of awareness, uneven distribution of empanelled hospitals, shortage of healthcare, infrastructure and equipment, shortage of doctors and other human resources. The empanelled private hospitals also have certain issues, which they voice to many of us, Member of Parliament, namely, reimbursement, delay in payments, complaints of low package rates and cumbersome process and procedures. Some very, very serious issues regarding the implementation have come to the fore after a CAG report on the performance audit of the Ayushman Bharat Yojana was made. According to this report, not only are there invalid names and unrealistic date of births of lakhs of beneficiaries, but also issuance of duplicate PM-JAY IDs, ineligible households which have got registered as beneficiaries, to whom crores of money has already gone from the Government coffers. Sir, in addition, the Report reveals that the benefit of the scheme has got extended to people, who are dead, shown to have availed treatment after such